

आकाशवाणी चंडीगढ़

28 अप्रैल 2025, समय 1810

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही है।
- भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया।
- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द पूरे भारत में पूरी तरह लागू किया जाएगा।
- 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्यों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री व आला अधिकारियों के साथ राज्य के वित्त मामलों व रणनीतियों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही है। पहले चरण में 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीन क्षेत्रों में दिये जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पूर्व संध्या पर सरकार ने 139

पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें सात पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं।

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समा टीवी, आर्य न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूट्यूब चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित चैनलों के 6 करोड़ तीस लाख से अधिक दर्शक हैं। सरकार ने हमले पर बी.बी.सी. की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत के बी.बी.सी. प्रमुख को देश की भावनाओं से अवगत कराया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए बी.बी.सी. को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा आगे भी बी.बी.सी. की रिपोर्टिंग पर नज़र रखी जाएगी।

हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश में बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्यपाल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद) और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त

तत्वावधान में “शिक्षक, शिक्षा में परिवर्तन -विकसित भारत 2047 की दिशा में” विषय पर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना और क्रांति पैदा करेगी, जिससे भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है। यदि हमें 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की भूमिका के महत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक न केवल ज्ञान का संचारक होता है, बल्कि वह चरित्र निर्माण का भी शिल्पकार होता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार की गई नई शिक्षा नीति-2020 इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, बहु-विषयक, गुणात्मक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है।

उन्होंने कहा --

राज्यपाल ने शिक्षकों से अपील की कि वे 'डिजिटल ज्ञान बैंक' बनें और विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचारों से जोड़कर विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि देश और समाज के भविष्य के निर्माण के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय भी “शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में” रखा गया है।

उन्होंने बताया –

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द पूरे भारत में पूरी तरह लागू किया जा रहा है। इसके लिए 7 हजार प्रतिक्रियाएं ली गई हैं। इन सुझावों के आधार पर शिक्षा नीति में परिवर्तन किए जाएंगे। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चन्द्र शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर, तर्कसंगत ढंग से सोचने वाले, काम करने वाले, मानवतावादी, साहसी और रचनात्मकता से युक्त युवा तैयार करना है। सम्मेलन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के कुलपति एवं निदेशक भाग ले रहे हैं।

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्यों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक

में हरियाणा के आर्थिक ञांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई।आयोग को हरियाणा के मजबूत आर्थिक प्रबंधन और भविष्य के रोडमैप को रेखांकित करती प्रस्तुति दी गई। आयोग को बताया गया कि केंद्र से कम हिस्से के बावजूद राज्य का राजकोषीय घाटा और देनदारियां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर ही रही है।राज्य सरकार ने संतुलित, समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आयोग को राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, प्रगतिशील सुधारों और रणनीतिक निवेशों के बारे में आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सुझाव दिया कि व्यापक पैमाने पर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को विशेष निधि मिलनी चाहिए।मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हरियाणा के लिए धन के विभाजन के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेजों का संग्रह प्राप्त किया। कलाम के परिवार द्वारा कागजात सौंपे जाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह भी आयोजित किया गया।इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल मौजूद थे। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पूर्व राष्ट्रपतियों से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह एकत्र करने की प्रक्रिया में है।